

प्रेषक,

अभरिन्द सिन्हा,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग

देहरादून दिनांक: 18 जनवरी 2010

विषय:- कोन्हापुरोनिर्माणित योजना "स्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के अन्तर्गत योजनाओं हेतु धनराशि।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं० 1173/लउसि०/ ए०आई०बी०पी०/ 2009-10 दिनांक 29.11.2009 एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2007, 8 फरवरी 2008 एवं 14 अगस्त 2008 तथा दिनांक 23 मार्च 2008 के क्रम में शासनादेश दिनांक 13 नवम्बर 2007, 21 फरवरी 2008, 11 अप्रैल 2008, 25 जून 2009 एवं दिनांक 30 अगस्त 2009 के द्वारा स्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए संपत्ति 60035.8850 लाख लागत की स्वीकृत 098 घाटू योजनाओं हेतु कोन्हापुरोनिर्माणित के रूप में प्रायः धनराशि को क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि घाटू वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत बजट प्राधिकरण के सम्मुख कथित 732.53 लाख (सप्टेमा खात करीब बत्तीस लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु की राजस्वपत्र महोदय आपके नियंत्रण पर गिम्ब शर्तों के अधीन प्राविष्ट सिधे जाने की सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमति की जा रही धनराशि का व्यय योजनाओं की प्रस्तावनाओं एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1144/11-2007-04(24)/2008 दिनांक 04.10.2007 में विहित शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध पूर्ण करने हेतु ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्वय विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्य के प्राप्तिजनक सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त निर्गत स्वीकृति का व्यय प्रथमिकता के अन्तर्गत उन्हीं योजनाओं में किया जाय जो प्रथमता शर्तों से शासनादेश पूर्ण हो जाय तथा उक्तानुसार निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण हुई योजनाओं की सूची रखने को उपलब्ध करायी जाय।
5. उक्त व्यय में बजट मैन्युअल वित्तीय, हस्तपुस्तिका, हैण्डर/गुडेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा वित्तव्यय के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों-निर्देशों एवं उत्तराखण्ड अधिपति (प्रखोलेक्ट) नियमावली 2008 का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि के सम्मुख व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक

क्रमसं:.....2

प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. स्वीकृत की जा रही स्मार्टरि का उपभाग निर्धारित समयान्तर्गत तक कर लिया जाय कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोजित प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।
9. एआईडीसीआईडी की योजनाओं पर कब कबले समय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाय।
10. प्रत्येक योजना पर डिप्लोमेट/साईन बोर्ड अपना सुनिश्चित किया जाय जिस पर योजना का नाम योजना की लागत, स्वीकृति का वर्ष, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि आदि विवरण अंकित हो।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय बालु विलीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखासीपक 4702-मध्य सिमेंट पर पुर्जीगत करिव्यय 800-अन्य व्यय-01-केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिष्ठागत योजना (90 प्रतिशत फंडिंग), 0104-व्ययित सिमेंट सल योजना (90 प्रतिशत केंद्रीय सहायता), 24- बृहद् निर्माण कार्य के नामे आला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के असाहाय्य संख्या-335(p)/XXVII-4/09 दिनांक 05.01.2010 में ज्ञात उनकी गतिविधि से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेंद्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या 69/11-2010-04(24)/2008/तद्विनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, औद्योगिक मोटर्स बिल्डिंग, सहायपुर रोड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मध्य मंत्री सचिवालय।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. कजट, राजकोषीय नियोजन व ससाधन निदेशालय सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मार्ग फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एसएसएलटोलिया)
अनु सचिव